सब्सिडी सुधारेगी चीनी मिलों की सेहत

40 लाख टन के कोटे का निर्यात होने पर उद्योग को होगी 13,200 करोड़ रुपये की आमदनी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 16 जून

कच्ची चीनी पर निर्यात सब्सिडी योजना सितंबर 2015 तक बढ़ाने से मिलों की नकदी आय बढ़ने का अनुमान है, जिससे इस वित्त वर्ष में उनकी वित्तीय स्थिति सुधरने की संभावना है। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने कच्ची चीनी के निर्यात पर सब्सिडी योजना सितंबर 2015 में चालू पेराई सीजन 2014-15 खत्म होने तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत सरकार चीनी मिलों को निर्यात पर 3,300 रुपये प्रति टन की सब्सिडी देती है। सरकार ने 40 लाख टन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। चीनी उद्योग का मानना है कि देश में 40 लाख टन चीनी सरप्लस है। इस योजना का मकसद देश के खस्ताहाल चीनी उद्योग को उबारना है।

एक मोटा अनुमान लगाया गया है कि निर्यात सब्सिडी की अवधि में प्रस्तावित बढ़ोतरी से सितंबर 2015 तक के 15 महीनों के दौरान चीनी उद्योग को 13,200 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इस राशि में से 1,200 करोड़ रुपये सीधे किसानों को मिलने का अनुमान है, जबकि शेष 12,000 करोड़ रुपये चीनी मिलों को उनके सब्सिडी फंड के दावे के रूप में मिलेंगे।

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा, 'अगर मिलें आवंटित 40 लाख चीनी का भारतीय बाजारों के मुकाबले ऊंची दरों पर निर्यात करने में सफल रहीं तो इस साल उनकी वित्तीय सेहत में सुधार आएगा।' पिछले कुछ महीनों के दौरान वैश्विक बाजारों में चीनी की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है, जिससे निर्यात करना फायदेमंद हो गया है।

आईसीई पर कच्ची चीनी का जुलाई वायदा 16.67 सेंट पर आठ सप्ताह के निचले स्तर आने के बाद करीब 2 फीसदी चढ़ा है। वहीं लाइफ पर सफेद चीनी का अगस्त वायदा शुक्रवार को 2 फीसदी बढ़त के साथ 465.2 डॉलर प्रति टन पर बंद हुआ। विश्व के सबसे बड़े चीनी निर्यातक ब्राजील में निर्यात होने वाली चीनी की लदाई के इंतजार में खड़े जहाजों की तादाद में पिछले सप्ताह की तुलना में करीब 50 फीसदी बढ़ोतरी से चीनी की मांग बढ़ने का संकेत मिल रहा है, जिससे कीमतें बढ़ी हैं। अगर वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतें वर्तमान स्तर से थोड़ी भी बढ़ीं तो भारत से निर्यात करना लाभप्रद रहेगा। बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 31 मार्च 2014 को समाप्त 12 महीनों की अवधि के दौरान चीनी उद्योग को कुल 3,200 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जबकि इससे पिछले साल की समान अवधि में उद्योग को 20 करोड़ रुपये का मामूली लाभ हुआ था।

एसवीएस सिक्योरिटीज के रणनीतिकार हरीश वासुदेवन ने कहा, 'भारत का चीनी उद्योग मंदी का शिकार है। सरकार की प्रतिकूल नीतियों के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान चीनी उद्योग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। लेकिन निर्यात सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाने से इस साल फिर उद्योग फलेगा-फूलेगा और इस मुनाफे से कई कंपनियां ऋण-मुक्त हो जाएंगी।'

इस साल चीनी मिलों की बिक्री उत्पादन के बराबर 242 लाख टन रहने की संभावना है। भारत में नए सीजन की शुरुआत में बचा हुआ स्टॉक पिछले साल की तुलना में 18 से 20 लाख टन कम रहेगा, लेकिन फिर भी 15-20 लाख टन चीनी का सरप्लस रहेगा, जिसका सही मौका आने पर निर्यात किया जा सकता है। खाद्य मंत्रालय के निर्यात सब्सिडी को 3,300 रुपये प्रति टन से घटाकर 2,277 रुपये करने से चीनी निर्यात की रफ्तार मंद पड़ी है। हालांकि नई सरकार ने 3,300 रुपये प्रति टन की सब्सिडी फिर बहाल कर दी है। वासुदेवन ने कहा कि सरकार ने चीनी उद्योग को पटरी पर लाने के लिए सुधारवादी कदम उठाए हैं। इससे किसानों का हित जुड़ा हुआ है और यह भारत की ग्रामीण आय से जुड़ा मसला है, लेकिन सरकार के उपायों का चीनी उद्योग को भी फायदा मिलेगा।

मिलों के सुहाने सपने

- निर्यात सब्सिडी की अवधि बढ़ाने से चीनी उद्योग को 13,200 करोड़ रुपये की नकदी मिलेगी
- इसमें से 1,200 करोड़ रुपये का किसानों को और शेष 12,000 करोड़ रुपये मिलों को मिलेंगे
- वैश्विक मांग बढ़ने से वैश्विक कीमतें निर्यात के अनुकूल रहेंगी
- स्वीकृत 40 लाख टन के निर्यात से इस साल उद्योग की वित्तीय सेहत में आ सकता है सुधार
- वित्त वर्ष 2014 में चीनी उद्योग को 3,200 करोड़ रुपये का घाटा, इस साल आमदनी बढ़ने से नुकसान की होगी भरपाई

बिजनेस स्टैन्डर्ड
17/6/14